Funds Provided to States under JRY

2802. SHRI JOYANTA ROY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of the funds provided to States under Jawahar Rozgar Yojana; and

(b) the State-wise details of funds actually utilised out of this so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) the Jawahar Rozgar Yojana (JRY) is being implemented from Ist April, 1989. The details of funds provided to the States under JRY from 1989-90 to 1994-95 are given in Annexure [*See* Appendix 173, Annexure No. 58]

(b) The Statewise details of funds utilised by the States is given in Annexure [*See* Appendix 173 Annexure No. 59]

ग्रामीण भूमि से संबंधित रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण

2803. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण भूमि से संबंधित रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करने हेतु एक अलग केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत 31 जनवरी, 1995 तक हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार इस कार्य में और तेजी लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में (ग्रामीण विकास विभाग) राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) जी, हां।

(ख) 1988-89 के दौरान 8 राज्यों में सिर्फ एक जिले के लिए 100% वित्तीय सहायता भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना प्रारंभ में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। 1989-90 से 1991-92 के दौरान इस योजना को 13 और जिलों में कार्यान्वित किया गया था और परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। इसके उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए इस कार्यक्रम को अब भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की बारे में अलग से केन्द्रीय प्रयोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 48 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। 31 जनवरी, 1995 तक राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 24.28 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में 102 परियोजना जिले शामिल हैं।

योजना के अन्तर्गत कवर किए गए जिलों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) यह एक निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है तथा आने वाले वर्षों में इसका विस्तार कर इसे जारी रखने का प्रस्ताव है। 1994-95 से यह योजना इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के साथ अनुपूरक आधार पर कार्यान्वित की जा रही है जिसके लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से वित्तीय और तकनीकी सहयोग लिया जाएगा।

विवरण

भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के बारे में परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत जिलों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना जिले
1.	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	(1) रंगारेड्डी
		(2) करीमनगर
		(3) कुडप्पा
		(4) नेल्लूर
		(5) करनल
		(6) पश्चिम गोदावरी
		(7) अनन्तपुर
		(8) श्रीकाकुलम
2.	असम	(1) सोनितपुर
		(2) कामरूप
		(3) नौगोंग
		(4) करीमनगर
		(5) दरांग

1	2	3
3.	बिहार	(1) पूर्वी सिंहभूम
		(2) संथाल परगना
		(3) दुमका
		(4) गया
		(5) मुजफ्फरपुर
		(6) लोहरदगा
		(7) जहानाबाद
4.	गुजरात	गांधीनगर
5.	गोवा	सम्पूर्ण राज्य
6.	हरियाणा	(1) रेवाड़ी
		(2) सिरसा
		(3) गुड़गांव
		(4) रोहतक
		(5) अम्बाला
7.	हिमाचल प्रदेश	(1) कांगड़ा
		(2) किन्नौर
		(3) सिरमौर
		(4) हमीरपुर
		(5) कुल्लू
		(6) सोलन
8.	जम्मू एवं कश्मीर	(1) श्रीनगर और जम्मू
		(2) कथुआ
		(3) बड़गाम
9.	कर्नाटक	(1) गुलबर्गा
		(2) मैसूर
		(3) रायचूर
10.	केरल	(1) तिरूअनंतपुरम
		(2) कोट्टयाम
		(3) आलापुझा
11.	मध्य प्रदेश	(1) मोरैना
		(2) होशंगाबाद
		(3) इन्दौर
		(4) सीधी
		(5) विदिशा
		(6) जबलपुर
		(7) भोपाल
12.	महाराष्ट्र	(1) वर्धा
		(2) अमरावती
		(3) नासिक
		(4) औरंगाबाद
		(5) बम्बई
		(6) नागपुर
		(7) पुणे
13.	मणीपुर	(1) इम्फाल
		(2) बिशनपुर
		(3) थौबल
14.	मिजोरम	आइजॉल
15.	उड़ीसा	(1) मयूरभंज
		(2) डेंकनाल
		(3) गंजाम
16.	पंजाब	(1) रोपड़
		(2) जालंधर
		(3) भटिंडा
		(4) कपुरथला
		(5) संगरूर
17.	राजस्थान	(1) डूंगरपुर
		(2) बाड़मेर
		(3) जयपुर
		(4) जोधपुर
		(5) कोटा
18.	सिक्किम	सम्पूर्ण राज्य
19.	तमिलनाडु	(1) सेलम
		(2) त्रिचूरापल्ली
		(3) तिरूनेल्वेली
		(4) रामानंतपुरम
20.	त्रिपुरा	(1) उत्तरी जिला
		(2) दक्षिणी त्रिपुरा
		(3) पश्चिमी त्रिपुरा
21.	उत्तर प्रदेश	(1) देवरिया
		(2) इटावा
		(3) आगरा
		(4) मुरादाबाद
		(5) मैनपुरी
		(6) इलाहाबाद
		(7) अलीगढ़
		(8) बरेली
		(9) गोंडा
		(10) हरदोई
		(11) नैनीताल
22.	पश्चिम बंगाल	(1) वर्धवान
		(2) हुगली
		(3) जलपाईगुड़ी
		(4) नादिया
		(5) हावड़ा
23.	दादर व नगर हवेली	सम्पूर्ण केन्द्र शासित क्षेत्र
24.	दिल्ली	सम्पूर्ण केन्द्र शासित क्षेत्र
25.	पांडेचेरी	सम्पूर्ण केन्द्र शासित क्षेत्र
		कुल: 102 परियोजनाएं